

## काका खट्टर का सुशासित हरियाणा ? वाह रे वाह, शिक्षा विभाग हरियाणा!

भिवानी (म.मो.) विद्यालय को नियम से संचालन करने पर विद्यालय प्राचार्य की पिटाई भी हुई और विभाग द्वारा आरोप पत्र भी दिया गया।

अब हरियाणा के अन्य विद्यालय प्राचार्य और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख संभल कर कार्य करें वरना ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाने पर उनको भी ये दिन देखना पड़ सकता है।

माजरा भिवानी के राजकीय गलर्स सीनियर सेकेंडरी विद्यालय धारहरू का है। यहाँ के तत्कालीन प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा जो अभी टोहना में कार्यरत हैं, के कुछ महीने पहले एक प्राध्यापिका द्वारा पिटाई करने की रिपोर्ट हुई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा श्री गणेशन ने प्राध्यापिका को निलम्बित कर दिया था और उसे विभागीय आरोप पत्र भी विभाग द्वारा जारी किया गया था।

अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक आरोप पत्र भी अजीबो गरीब है।

1. प्राचार्य आदतन स्टाफ एवं अध्यापकों को उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एडवर्स रिपोर्ट की धमकी देता है।

2. प्राचार्य ने बिना कारण के पिटाई करने वाली अध्यापिका को planation letter जारी कर परेशन किया है।

खास बात ये है कि इस पिटाई की घटना से पहले प्राचार्य के खिलाफ किसी भी स्टाफ की कोई शिकायत कही भी दर्ज नहीं है बल्कि गाँव के लोगों ने पिटाई करने वाली प्राध्यापिका के खिलाफ कार्यवाई की मांग की थी।

अभी अगर संस्थानों के प्रमुख अपने कनिष्ठ से बना कर नहीं चलते हैं या फिर ज्यादा अनुशासन या परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे तो किसी कर्मचारी से पिटाई भी हो सकती है साथ में विभाग द्वारा आरोपित भी किया जा सकता है।



## बैप्टिस्ट चर्च भूमि घोटाले में लिपिक निलम्बित, तहसीलदार के खिलाफ जांच शुरू

भिवानी (म.मो.) रजिस्ट्री के चर्चित फर्जीवाड़े पर भिवानी के डिप्टी कमिशनर नरेश नरवाल ने अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाई की है।

गैरततलब है कि भिवानी के लोहड़ में स्थित बैप्टिस्ट मिशनरी सोसायटी कॉर्पोरेशन की विवादित जमीन वसीका नं. 6920 दिनांक 05-00-2022 की फर्जी रजिस्ट्री से संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन, चाण्डीगढ़ के माध्यम व अन्य आमजन से प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

अतिरिक्त उपायुक्त कम-जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त द्वारा तुरन्त प्रभाव से तहसीलदार, जो अन्य संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को विभागीय कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की और गई है। रजिस्ट्रेशन लिपिक को दिनांक 21-10-2022 के तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियमावली-2016 के अन्तर्गत नियम-07 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दिये गये थे।

अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी की जांच रिपोर्ट के वर्णन अनुसार संबंधित कानूनगों व पटवारी ने माननीय कलौक्टर भिवानी के न्यायालय से बैप्टिस्ट मिशनरी सोसायटी कॉर्पोरेशन के हक में दिये गये फैसला दिनांक 29-08-2022 पर तथ्यों व दस्तावेजों की बगैर पुष्टि किए व उपरोक्त फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील अवधि (30 दिन) के प्रावधान को अनदेखा करते हुए इन्तकाल का अवैध इन्ड्राज किया गया। जिसके आधार पर उपायुक्त द्वारा उपरोक्त कानूनगों व पटवारी को तुरन्त निलम्बित करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियमावली-2016 के अन्तर्गत नियम-07 तहत चार्जशीट करने के आदेश



दिये गये हैं।

वसीका नं. 6920 दिनांक 05-09-2022 के पंजीकरण के दौरान ओमबीर सिंह नम्बरदार निवासी गांव देवसर बतौर गवाह उपस्थित हुआ है, जबकि उक्त वसीका नं. 0 भिवानी लौहड़ क्षेत्र के अन्तर्गत है। ओमबीर सिंह नम्बरदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरकार की हिदायतों को अनदेखा करते हुए संबंधित प्रोपर्टी व दोनों पक्षों की पुष्टि की है। जिसके संबंध में उपायुक्त द्वारा ओमबीर नम्बरदार के खिलाफ कार्यवाही आरम्भ करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जगदीश सचदेवा विलेख लेखक व सज्जन वर्मा नोटरी पब्लिक के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त की जांच रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त विलेख लेखक व नोटरी पब्लिक की कार्यशैली सन्देहप्रस्त दर्शाई गई है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने वारे सिफारिश की है। जिस पर संज्ञान लेते हुए प्राकृतिक न्याय अनुसार कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट

में कुछ अन्य गैर-निर्णायक कारक व विवादित प्रोपर्टी मामले में अपने विभिन्न हितों के साथ शामिल कुछ गैर-ईसाई व्यक्तियों की गहनता से जांच करवाने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित केस माननीय सिविल न्यायालय भिवानी व देश के अन्य न्यायालय में भी लम्बित है। अतः विषयाधीन मामले की गहनता से जांच करने हेतु सरकार को राजस्व विशेषज्ञ की सदस्यता सहित विशेष जांच दल (एसओआईटी०) गठित करने वारे सिफारिश की गई है ताकि समाज के हितों की रक्षा को मद्दनजर रखते हुए बैप्टिस्ट संगठन की संपत्ति वारे विवाद /मुद्दों के पीछे की वास्तविकता का पता लगाया जा सके।

सब रजिस्ट्रर व संयुक्त सब-रजिस्ट्रर भिवानी को निर्देश दिये कि विवादित वसीका नं. 6920 दिनांक 05-09-2022 के अस्वीकृति आदेश की रपट द्वारा खाना काफियत में इन्ड्राज करेंगे व सक्षम न्यायालय व अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेशों तक विवादित खसरा नंबर पर भविष्य के लिए तुरन्त प्रतिबन्ध लगायें। इसके अतिरिक्त भविष्य में सक्षम प्राधिकारी व सक्षम न्यायालय के निर्देश के बिना विवादित प्रोपर्टी सहित अन्य बीएमएस, बीएमएससी व बीसीटीए से संबंधित किसी भी सम्पत्ति दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करेंगे।

इसके अलावा जिले के समस्त सब-रजिस्ट्रर व संयुक्त सब-रजिस्ट्रर को हिदायत दी कि वसीका पंजीकरण के संबंध में सरकार के निर्देशानुसार सभी सब-रजिस्ट्रर व संयुक्त सब-रजिस्ट्रर रजिस्ट्रेशन लिपिक द्वारा की गई दस्तावेज की जांच पर भरोसा न करके स्वयं पंजीयक अधिनियम/नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के उपरान्त रजिस्ट्री दस्तावेजों को चिह्नित करके आगामी प्रक्रिया हेतु संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को अप्रेषित करेंगे।

## अरावली पहाड़ियों को कचरा घर बनाने में जुटी खट्टर सरकार : सेव अरावली

बराबर रहेगा कचरे को पहाड़ बनाना कचरे का निपायन नहीं है कचरे को सही तरीके से सही स्थान पर ठिकाने लगाना और पुर्ण उपयोग के लायक बनाना कचरे का सही निस्तारण है। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी इस विनती को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप वह अद्भुत शक्ति हैं जो सरकार और प्रशासन की आंखों को खोल सकते हैं?

सेव अरावली ट्रस्ट की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में जितेंद्र भड़ाना ने अपने विचार

व्यक्त किए साथ ही प्रशासन को कूड़ा निस्तारण के ऊपर जोर देने का सुझाव दिया। इसके अलावा कैलाश बिधुड़ी एडेवोकेट, कृष्ण रावत, पंकज ग्रोवर, कृष्ण जगिया, विरद गुप्ता, यश भड़ाना, राजू रावत, संजय रात, शालिनी बिष्ट, संवेदना, विकास थेरेजा, वीर भान वर्मा जी, धीरज झा, लकी भड़ाना, भगेंदर भड़ाना ऐडवोकेट, बिजेन्द्र मास्टर जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आप सभी का आज की इस विरोध प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

“हमारे लोकतंत्र की यह ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेलखाने में रहना चाहिए वे जिन्दगी-भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं।

-हरिशंकर परसाई

**केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।**

**मजदूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150  
IFSC Code : UBIN0545112  
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad**



Majdoor Morcha  
UPI ID: 8851091460@paytm  
Paytm: 8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.